भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2805
जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है
सीआरआईएफ का कार्यान्वयन

2805. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को राज्यों की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियां आवंटित की हैं,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास हेतु निधि के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार परियोजनाओं की संस्वीकृति और विशिष्ट परियोजनाओं और उन पर हुए व्यय, विशेषकर जहां आर्थिक महत्व के सड़क कार्य और अंतर्राज्यीय संपर्क संस्वीकृत किए गए हैं, की निगरानी के लिए उत्तरदायी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्य की सड़कों के विकास एवं रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधि आवंटित करता है।

(ख) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के परामर्श से सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास एवं रखरखाव के लिए निधि आवंटन हेतु मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है।

मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देना, अनुमोदित लागत से 10 प्रतिशत तक की अनुमेय अतिरिक्त लागत के साथ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी (टीएंडएफएस) , निधि जारी करते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ वर्ष के लिए उपार्जन/आवंटन के एक तिहाई का चक्रीय शेष बनाए रखना, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने से जुड़ी तिमाही किस्तों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निधि जारी करने के 7 दिनों के भीतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसियों (जैसे पीडब्ल्यूडी, सड़क निर्माण विभाग/निगम आदि) को आगे की निधि जारी करना, नियमित अंतराल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की परियोजना निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजनाओं की पहचान, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए गति शक्ति की रूपरेखा को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना आदि शामिल हैं।

सरकार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए उनसे प्राप्त प्रस्तावों तथा योजना के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निधि जारी करता है ।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किए गए व्यय/निधि के उपार्जन और निर्मुक्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित, अनुलग्नक में दिया गया है।

(ड.) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत अनुमोदित राज्य सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अनुमोदित			
राज्य	संख्या	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड रुपये में)
महाराष्ट्र	536	3,203	7,108
उत्तर प्रदेश	18	93	1,123

अनुबंध

सीआरआईएफ का कार्यान्वयन के संबंध श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे, श्री धर्मेन्द्र यादव और श्रीमती भारती पारधी द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2805 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किए गए व्यय/निधि के उपार्जन और जारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल हैं :-

राशि करोड़ रुपये में									
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.10.2024 तक)	
		उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	334.96	300.80	380.19	356.55	420.10	485.48	420.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	128.39	128.33	147.65	183.63	167.75	238.00	168.04	65.55
3	असम	143.80	77.51	169.64	122.82	194.65	223.24	193.55	117.51
4	बिहार	201.16	447.06	226.47	226.47	258.43	258.43	255.17	215.61
5	छत्तीसगढ़	245.74	230.29	281.12	86.92	320.19	353.60	322.62	85.34
6	गोवा	13.41	0.00	16.26	0.00	18.47	48.16	17.79	7.52
7	गुजरात	434.06	725.29	509.31	249.12	586.35	73.79	585.01	472.85
8	हरयाणा	177.05	163.71	197.73	0.00	205.63	108.60	203.31	105.03
9	हिमाचल प्रदेश	99.74	188.01	117.73	169.05	136.32	136.32	130.95	110.65
10	झारखंड	164.33	40.79	184.96	81.56	207.57	192.64	208.51	83.87
11	कर्नाटक	443.11	442.90	513.13	465.27	608.06	660.91	608.81	0.00
12	केरल	126.77	126.71	147.19	133.46	171.14	186.37	166.06	70.16
13	मध्य प्रदेश	556.21	622.93	632.99	573.96	719.10	778.13	721.61	647.56
14	महाराष्ट्र	683.80	390.27	783.19	1,084.15	886.63	886.63	891.52	376.66
15	मणिपुर	36.60	13.43	42.10	13.81	48.37	146.98	46.87	0.00
16	मेघालय	40.63	90.55	47.51	43.08	54.83	78.42	55.37	0.00
17	मिजोरम	33.14	22.06	38.20	10.96	43.62	35.60	43.86	0.00
18	नगालैंड	27.02	27.00	31.31	28.39	35.54	46.09	35.79	30.24
19	ओडिशा	298.67	535.07	340.95	313.52	387.41	423.41	392.13	165.67
20	पंजाब	149.41	193.35	176.96	106.84	195.33	72.04	195.97	53.92
21	राजस्थान	627.89	148.40	715.82	906.62	812.41	745.90	816.17	689.63
22	सिक्किम	12.06	25.78	14.09	17.04	16.27	28.04	16.18	13.67

राशि करोड़ रुपये में										
क्र.स.	राज्य/संघ क्षेत्र	राज्य		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.10.2024 तक)
23	तमिलनाडु	350.32	350.15	402.67	377.63	457.11	486.15	457.75	211.68	
24	तेलंगाना	262.01	261.88	304.27	275.89	335.09	366.38	335.58	141.77	
25	त्रिपुरा	18.49	33.76	21.23	19.42	23.94	25.92	24.01	7.98	
26	उत्तर प्रदेश	616.59	616.29	702.42	658.75	777.40	821.07	777.88	657.28	
27	उत्तराखंड	98.85	98.80	114.01	378.17	129.83	140.46	129.95	0.00	
28	पश्चिम बंगाल	213.97	287.06	240.31	217.90	275.67	298.08	272.75	115.23	
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.17	10.08	17.49	15.81	19.75	16.68	19.75	5.56	
30	चंडीगढ़	4.76	0	6.55	0.00	7.39	0.00	7.40	0.00	
31	दादरा एवं नगर हवेली	4.80	2.38	5.74	0.31	6.50	0.00	6.49	0.00	
32	दमन और दीव									
33	दिल्ली	27.20	0	32.06	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00	
34	जम्मू और कश्मीर	96.91	321.18	113.61	343.61	128.67	206.67	128.67	108.72	
35	लद्दाख	250.83	0.00	289.06	83.44	326.41	68.10	326.41	0.00	
36	पुदुचेरी	7.39	5.18	10.39	7.83	11.76	9.94	11.76	4.97	

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से प्राप्त राशि से अधिक है।

सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी निधि शामिल है